

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

धरम बीर

8 जून, 1998

[एस. सागर अहमद और जी. बी. पटनायक, जे.जे.]

सेवा कानून-एम. पी. औद्योगिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1985 आर. आर.-13,14-शैक्षिक योग्यता-सरकार नियुक्ति का तरीका और पद के लिए योग्यता निर्धारित कर सकते हैं-केवल अनुभव को शैक्षिक योग्यता के बराबर नहीं माना जा सकता है-नियुक्ति के बाद सरकारी सेवा केवल एक अनुबंध नहीं है, बल्कि पद पर लागू कानूनों और नियमों द्वारा शासित स्थिति में से एक है-जिस क्षमता में पद आयोजित किया जाता है अर्थात् तदर्थ/मूल क्षमता/अस्थायी स्थिति को प्रभावित करता है- स्थिति में परिवर्तन के लिए कानून या नियमों में प्रावधान, कोई सरकारी कर्मचारी इसका दावा कर सकता है-न तो अदालतें और न ही न्यायाधिकरण संविधि के अनिवार्य प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सहानुभूतिपूर्ण आधारों पर राहत प्रदान कर सकते हैं क्योंकि ऐसा आदेश संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत किए गए प्रावधानों को बदलने या संशोधित करने के बराबर होगा।

प्रत्यर्थी नए नियम जारी होने तक पदोन्नति के आधार पर तदर्थ आधार पर प्राचार्य का पद संभाल रहा था। उक्त नियमों के तहत प्राचार्य पद के लिए उम्मीदवार के पास

इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना था और चूंकि उसके पास कोई सा भी नहीं था, इसलिए उसे प्राचार्य पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसे उप-प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जिसे बाद में एम. पी. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने इस आधार पर याचिका को स्वीकार कर लिया कि पदोन्नत होने वालों के लिए डिप्लोमा/डिग्री की योग्यता आवश्यक नहीं थी। इसलिए ये अपीलें की जाती हैं।

राज्य द्वारा अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. प्रधानाचार्य के पद पर एक तदर्थ क्षमता में काम करने वाले प्रतिवादी ने कुछ प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया होगा लेकिन इसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके ज्ञान के बराबर नहीं माना जा सकता है। एक कम्पाउंडर, जो आधुनिक चिकित्सा में अभ्यास करने वाले डॉक्टर के साथ काफी लंबे समय तक बैठा रहता है, हो सकता है कि उसने विभिन्न बीमारियों या रोगों के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा का निरीक्षण करके कुछ अनुभव प्राप्त किया हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस प्रक्रिया से मानव शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान या औषध विज्ञान □□ □□□□□□□□ □□ किसी विशेष दवा या उसके दुष्प्रभावों की कार्रवाई का क्षेत्रका ज्ञान प्राप्त करता है। कम्पाउंडर, केवल अनुभव के आधार पर, किसी पद का दावा नहीं कर सकता है। विशेष रूप से एमबीबीएस या सर्जरी या चिकित्सा में अन्य उच्च डिग्री रखने वाले व्यक्तियों के लिए बना है। इसलिए, अनुभव का आग्रह विफल होना चाहिए। इसके अलावा, यह नियम 21 द्वारा प्रदान किए गए नियम को विशेष रूप से राज्यपाल में निहित करने के लिए शैक्षिक योग्यता से संबंधित नियम में ढील देने के बराबर होगा। इस शक्ति को न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा हड़पा नहीं जा सकता है।

2. यदि सरकार ने अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ पद सृजित करती है तो नियुक्ति का तरीका निर्धारित या योग्यताएँ जो उन पदों पर नियुक्त होने

से पहले उम्मीदवारों के पास होनी चाहिए, यह सरकार हो तय करेगी। योग्यता स्वाभाविक रूप से पदों की प्रकृति या सरकार द्वारा बनाई गई सेवा के अनुसार भिन्न होगी।

[524 - ई]

3. विचाराधीन प्रश्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य का पद है। सरकार ने इस पद के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा निर्धारित किया है। जिन लोगों के पास यह योग्यता नहीं है, उन्हें इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता का पद की प्रकृति के साथ सीधा संबंध है। प्रधानाचार्य के पास कक्षाएं लेने और छात्रों को पढ़ाने का अवसर भी पड़ सकता है। एक व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, वह संभवतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों को इंजीनियरिंग विषय और इसकी विभिन्न शाखाओं की तकनीकी □□□ □□□ को नहीं पढ़ा सकता है। एक दशक से अधिक समय तक विचाराधीन पद पर काम करने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त "अनुभव" को आवश्यक शैक्षिक योग्यता के बराबर नहीं माना जा सकता है □□ □□□□ □□□□ □□ पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त के रूप में एक उम्मीदवार को जरूरत है। **[524 - एफ-जी]**

4. यह याचिका कि न्यायालय का "मानवीय दृष्टिकोण" होना चाहिए और होना चाहिए एक दशक से अधिक समय से इस पद पर काम कर रहे व्यक्ति को परेशान न करना भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अदालतें शायद ही भावनात्मक अपीलों से प्रभावित होती हैं। वादकारी पक्षकारों को न्याय प्रदान करने में, न्यायालय न केवल संबंधित मामलों के गुण-दोष पर ध्यान देते हैं; वे समानताओं को संतुलित करने का भी प्रयास करते हैं ताकि उनके बीच पूर्ण न्याय हो सके। इस प्रकार न्यायालय हमेशा एक मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। तत्काल मामले में भी इस दृष्टिकोण से अलग नहीं चला गया। न्यायालय इस बात से पूरी तरह अवगत है कि प्रतिवादी ने काफी लंबे समय तक विचाराधीन पद पर काम किया, लेकिन यह केवल एक तदर्थ क्षमता में था, कि एक

चयनित उम्मीदवार जिसके पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता भी है, उपलब्ध है। इस स्थिति में, यदि प्रतिवादी को केवल "मानवीय दृष्टिकोण" की अपनी अवधारणा के आधार पर इस पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है तो यह एक विधिवत चयनित उम्मीदवार की कीमत पर होगा जो उस रोजगार से वंचित हो जाएगा जिसके लिए उसने प्रयास किया था और अंततः चयनित हुआ हो। वास्तव में, यह "मानवीय दृष्टिकोण" है जिसके लिए न्यायालय को चयनित उम्मीदवार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है ऐसे व्यक्ति से ऊपर जिसके पास अपेक्षित योग्यता भी नहीं है। न्यायालयों और न्यायाधिकरण के पास भी कोई शक्ति नहीं है कि सहानुभूतिपूर्ण विचार पर नियमों के अनिवार्य प्रावधानों की अवहेलना करें कि एक व्यक्ति, हालांकि आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है, को पद पर जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए केवल अपने अनुभव के आधार पर। ऐसा आदेश संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत सरकार द्वारा बनाए गए वैधानिक प्रावधानों को बदलने या संशोधित करने के समान होगा।

[523 - जी-एच; 524-ए-सी]

5. क्या कोई व्यक्ति किसी विशेष पद पर एक □□□□□□□□ क्षमता में है या केवल अस्थायी है या तदर्थ एक ऐसा प्रश्न है जो सीधे उसकी स्थिति से संबंधित है। यह सब नियुक्ति की शर्तों पर निर्भर करता है। यह किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए स्थिति के □□□□ : परिवर्तन का दावा करने के लिए खुला नहीं है जब तक कि वैधानिक नियमों में कुछ प्रावधानों द्वारा परिणाम की विशेष रूप से परिकल्पना की गई है। जब तक कि परिवर्तन के लिए सांविधिक नियमों में कोई प्रावधान न हो □□□□□□ □□□ किसी विशेष परिस्थिति में, यह किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए खुला नहीं है उस स्थिति से भिन्न स्थिति का दावा करने के लिए जो उसे □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ कोई बाद का चरणमें प्रदान की गई थी। इन सिद्धांतों को तत्काल मामले में लागू करते हुए, क्योंकि प्रत्यर्थी, स्वीकार्य रूप से, एक तदर्थ क्षमता में नियुक्त किया गया था, वह उस क्षमता में विचाराधीन पद पर बने रहेंगे। इसलिए, नियमों की घोषणा पर, प्राचार्य का पद

जो उनके पास था, उसे नियमित आधार पर भरा नहीं जा सकता था और खाली माना जाए। पदोन्नति द्वारा नियमित नियुक्ति करने के लिए उस पद पर, योग्य उम्मीदवारों पर विचार किया गया और उत्तरदाता □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ रखने वाला योग्य और उपयुक्त नहीं पाया गया प्रधानाचार्य के पद के लिए और परिणामस्वरूप उन्हें नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था उपाध्यक्ष के रूप में नियमित आधार पर क्योंकि उन्हें मुख्य रूप से इस कारण से कि उनके पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा नहीं था उस पद के लिए उपयुक्त पाया गया था । [522 - एफ-एच; 523-ए-बी]

रोशन लाल टंडन बनाम भारत संघ, [1968] 1 एस. सी. आर. 185; भारत और अन्य बनाम तुलसीराम पटेल, ए. आई. आर. (1985) एस. सी. 1416 = [1985] 3 एस. सी. सी. 398 = [1985] सप. 2 एस. सी. आर. 131 और दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस, ए. आई. आर. (1991) एस. सी. 101 = [1991] सप. 1 एस. सी. सी. 600 = [1990] सप. 1 एस. सी. आर. 142, पर निर्भर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 7333-34/1995

मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबल पुर के दिनांकित 19.4.94/2.1.95 निर्णय और आदेश से, जो कि टी. ए. सं. 510 /1988 और एम. ए. सं. 361/1994 में पारित किया गया।

सुश्री मधुर ददलानी, एस. के. अग्निहोत्री और अशोक के. सिंह याचिकाकर्ता के लिए

उत्तरदाता के लिए के. स्वामी, ए राघुनाथ और सुश्री प्रभा स्वामी।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

एस. सागर अहमद, न्यायाधिपति

1. "नहीं, केवल अनुभवात्मक ज्ञान, इंजीनियरिंग में डिग्री के बराबर नहीं है।" इस नकारात्मक तर्क का हमारा सकारात्मक जवाब है कि प्रतिवादी, हालांकि आवश्यक योग्यता नहीं रखता है, अपने अनुभव के आधार पर वैध रूप से प्रिंसिपल, आई. टी. आई. का पद धारण करता है।

2. तथ्य, उठाए गए प्रश्न और उन पर निष्कर्ष इसके बाद दर्ज किए जाते हैं।

3. प्रत्यर्थी को 3.12.1957 पर वरिष्ठ प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 13.12.1959 पर पर्यवेक्षक प्रशिक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद उन्हें फोरमैन और फिर समूह प्रशिक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया।

4. 15.6.1976 पर, प्रत्यर्थी को प्राचार्य, कक्षा II के रूप में पदोन्नत किया गया था छह महीने की अवधि या उस पद के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत चुने गए उम्मीदवार उपलब्ध होने तक (जो भी पहले हो)। प्राचार्य, कक्षा II का पद एक नव सृजित पद था और इसे एम. पी. औद्योगिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1965 में शामिल नहीं किया गया था और चूंकि उस पद पर नियुक्ति या भर्ती का तरीका लगभग 1985 तक निर्धारित नहीं किया गया था, प्रत्यर्थी ने विभिन्न स्थानों पर उस पद पर काम करना जारी रखा जहां उनका समय-समय पर तबादला किया गया था।

5. 28.6.1985 पर, मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1995 (संक्षेप में, नियम) संविधान के अनुच्छेद 303 के तहत सरकार द्वारा बनाए गए ,

को प्रकाशित किया गया था। इन नियमों से एम. पी. औद्योगिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1965 को बदला गया। नए नियम में प्रावधान किया कि प्राचार्य, ग्रेड II के पद 75 प्रतिशत की सीमा तक सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 25 प्रतिशत की सीमा तक पदोन्नति से भरे जायेंगे। पदोन्नति के माध्यम से भर्ती का तरीका नियम 13 से 18 तक बताया गया था

6. नियम बनाए जाने और विधिवत घोषित किए जाने के बाद, विभागीय पदोन्नति समिति ने नवंबर, 1985 में प्रधानाचार्य, वर्ग II के पद पर नियमित पदोन्नति के लिए योग्य उम्मीदवार पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। चूंकि प्रत्यर्थी के पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा नहीं था प्राचार्य, वर्ग II के पद के लिए निर्धारित नियमों के तहत, समिति ने उन्हें केवल उप-प्राचार्य के पद के लिए उपयुक्त पाया गया और इसलिए, दिनांकित 12.06.1986 के आदेश द्वारा, उन्हें पदोन्नत किया गया और उप-प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिलाई के रूप में नियुक्त किया गया।

7. यह आदेश ही है जो इस लंबी मुकदमेबाजी का आधार है क्योंकि उत्तरदाता जो पहले से ही प्राचार्य वर्ग II के रूप में काम कर रहा था उक्त आदेश को प्रत्यावर्तन के आदेश के रूप में वर्णित करता है।

8. प्रत्यर्थी ने इस आदेश को रिट याचिका में एम. पी. उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी जिसे एम. पी. राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, जबलपुर को स्थानांतरित कर दिया गया था और ट्रिब्यूनल ने अपने दिनांक 19.4.1994 के फैसले से याचिका को अनुमति

दी इस निष्कर्ष के साथ कि शैक्षिक योग्यता रखने की आवश्यकता प्राचार्य पद के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता यह केवल सीधी भर्ती पर लागू होता था और इस तरह की पदोन्नति पर नहीं और जैसे कि प्रतिवादी के पास इंजीनियरिंग में न तो डिग्री थी और न ही डिप्लोमा अभी भी प्रिंसिपल, कक्षा II के रूप में पदोन्नत होने का हकदार था।

9. यह इस स्पष्ट रूप से अतार्किक तर्क का तर्क है जो होना है जिसकी इस अपील में हमारे द्वारा जांच कीजानी है।

10. नियुक्तियाँ, या तो प्रत्यक्ष आवश्यकता द्वारा या पदोन्नति द्वारा, प्राचार्य, वर्ग I या वर्ग II के पद पर, जैसा कि पहले बताया गया है, 1985 में घोषित नियमों के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया है। नियम 7 जो "सेवा में नियुक्ति" से संबंधित है, निम्नानुसार प्रदान करता है:

"7. सेवा में नियुक्ति.- इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई नियुक्ति नियम 6 में निर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक द्वारा चयन के बाद के अलावा नहीं की जाएगी।"

11. भर्ती के तरीके को नियम 6 में इंगित किया गया है जिसे उद्धृत किया गया है नीचे:

"6. भर्ती की विधि.- (1) इनके प्रारंभ होने के बाद सेवा में भर्ती, जब तक, निम्नलिखित विधियों से नहीं होगी; अर्थात्:-

(ए) चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(बी) अनुसूची IV का कॉलम (2); में निर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा

(सी) मूल रूप से नियुक्त व्यक्तियों के निर्दिष्ट सेवा में निर्दिष्ट पद पर स्थानांतरण द्वारा

(2) उप-नियम (1)के खंड (बी) और (सी) के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या कर्तव्य पदों की संख्या की अनुसूची II में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगा।

(3) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली भर्ती की विधि या तरीके, जिन्हें भर्ती की किसी विशेष अवधि के दौरान भरने की आवश्यकता हो सकती है, और प्रत्येक विधि द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि सरकार की राय में, सेवा की अनिवार्यता की आवश्यकता है, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग में सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, ऐसी पद्धति अपना सकती है। या उक्त उप-नियम में निर्दिष्ट के

अलावा सेवा में भर्ती के तरीके, जैसा कि इस संबंध में जारी आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।"

12. सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की पात्रता की शर्तें नियम 8 में निर्देशित हैं। नियम का पहला भाग "आयु" की आवश्यकता से संबंधित है। उप- नियम (2) जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित करता है, नीचे उद्धृत किया गया है:

(2) शैक्षिक योग्यताएँ - उम्मीदवारों के पास सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची III में दिखाया गया है :

बशर्ते कि-

(क) अपवादात्मक मामलों में आयोग, सरकार द्वारा सिफारिशों पर, किसी भी उम्मीदवार को जो चयन के लिए उपस्थित होने के लिए योग्य माना जाता है जिनके पास इस खंड में विहित हालांकि कोई योग्यता नहीं है ,अन्य संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की है एक मानक के साथ जो आयोग की राय में चयन के लिए उम्मीदवार पर विचार को उचित ठहराता है।

(ख) उम्मीदवारों के, जो अन्यथा योग्य हैं लेकिन जिन्होंने उन विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री ली है जो सरकार से विशेष रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, आयोग के निर्देश पर चयन के लिए भी विचार किया जा सकता है।

13. अनुसूची III में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा है।

14. नियम 13 पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान करता है। नियम 14 पदोन्नति के लिए पात्रता प्रदान करता है। दोनों नियम नीचे उद्धृत किए गए हैं:

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति - (1) वहाँ एक अनुसूची IV में उल्लेखित सदस्यों से बनी समिति का गठन किया जाएगा योग्य उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु।

(2) समिति की बैठक आम तौर पर एक वर्ष से अधिक अंतराल पर नहीं होगी।

(3) ऐसे पदों पर पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रिक्तियाँ जिनमें पदोन्नति का प्रतिशत $33 \frac{1}{3}$ या अधिक है, जैसा कि अनुसूची II में निर्दिष्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगी। क्रमशः जनजातियाँ जो नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति हेतु पात्र हैं।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति की प्रक्रिया सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग " को जारी किए गए निर्देश के अनुसार होगी

14. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें - उप नियम (2) के प्रावधानों के अधीन की समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष जनवरी के पहले दिन तक इतने वर्षों की सेवा, चाहे वह कार्यवाहक हो या मूल क्षमता ,अनुसूची IV के कॉलम (3) में और उप-नियम (2)के प्रावधानों के अनुसार विचार क्षेत्र के भीतर हैं।

बशर्ते कि आपातकाल आयोग और अल्पकालिक सेवा आयोग के पदमुक्त किए गए अधिकारियों की सेवाएं उनकी सेवा -नियुक्ति के बाद उस तारीख से गिना जाएगा

जिस तारीख से उनके पास है सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन सं. 2266/1987/1 (3) 67 के अनुसार सेवा दिनांकित 21 अक्टूबर, 1967।

बशर्ते कि इस नियम के तहत कोई भी कनिष्ठ व्यक्ति की चयन ग्रेड पदोन्नति के केवल निर्धारित कार्यकाल को पूरा करने के आधार पर उससे वरिष्ठ व्यक्ति की वरीयता की तुलना में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) चयन का क्षेत्र आम तौर पर सात गुना तक सीमित होगा चयन सूची में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या "योग्यता-सह-वरिष्ठता" आधार पर भरे जाने वाले पद और चयन सूची में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या "वरिष्ठता-सह-योग्यता" के आधार पर भरे जाने वाले पद के अनुसार;

बशर्ते कि यदि इस प्रकार निर्धारित क्षेत्र में आवश्यक संख्या में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, तो लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करके समिति द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है।

15. नियम 15 में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए अधिकारियों की सूची तैयार करने का प्रावधान है। नियम 16 के अनुसार इस सूची को आयोग को स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए। एक बार जब सूची आयोग द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो यह नियम 17 द्वारा विचारित चयन सूची बन जाती है। नियम 18 में प्रावधान है कि ई सेवा में नियुक्ति चयन सूची से की जाएगी और चयन सूची में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति करते समय, आदेश दिया जाएगा। जिसमें उनके नाम चयन सूची में दिखाई देते हैं, नियम 18 के उप-नियम (1) के परंतुक में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर

इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। चूंकि नियम 14 जो पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों को निर्धारित करता है, विशेष रूप से अनुसूची IV को संदर्भित करता है, के प्रयोजनों में पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा सेवा के वर्षों की संख्या पूरी की जानी चाहिए, अनुसूची IV के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं: -

" अनुसूची IV

(नियम 13 देखें)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति होनी है	पात्रता के लिए न्यूनतम अनुभव	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति होनी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जनशक्ति नियोजन विभाग	मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित सेवा)	3 वर्ष	उप प्रशिक्षु सलाहकार(कनिष्ठ) प्राचार्य वर्ग I	निदेशक रोजगार व प्रशिक्षण ,मध्य प्रदेश सदस्य

	वर्ग II			
	<p>ग्रुप</p> <p>इंस्टिट्यूटर/तकनीकी</p> <p>सहायक/जूनियर सलाहकार, अप्रेंटिसशिप/मिल राइट फॉर्मन/अधीक्षक,</p> <p>प्रशिक्षण में शर्त यह है कि उनके पास अनुसूची III के कॉलम (5) में निर्दिष्ट तकनीकी और शैक्षणिक योग्यताएं हों।</p>	<p>3 वर्ष</p> <p>10 वर्ष</p>	<p>प्राचार्य वर्ग II</p> <p>उप -प्राचार्य</p>	

	गुप इंस्पेक्टर/तकनी की सहायक/जूनिय र सलाहकार अप्रेंटिसशिप/मि मिल राइट फोरमैन/अधीक्ष क, तकनीकी, जिनके पास डिग्री /डिप्लोमा नहीं			
--	---	--	--	--

16. इस प्रकार अनुसूची IV में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि समूह प्रशिक्षक / तकनीकी सहायक/कनिष्ठ सलाहकार आदि जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो वे प्राचार्य, द्वितीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। आवश्यकता यहीं नहीं रुकती है। यह आगे कहता है, "बशर्ते उनके पास अनुसूची III के कॉलम (5) में निर्दिष्ट तकनीकी और शैक्षिक योग्यता हो।" अनुसूची IV के साथ-साथ अनुसूची III के कॉलम (5) के साथ नियम 13 और 14 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानाचार्य, कक्षा

II के पद के लिए, पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए संबंधित अधिकारी को न केवल 3 साल की सेवा में होना चाहिए, बल्कि अनुसूची III के कॉलम (5) में निर्धारित तकनीकी और शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए, अर्थात् उनके पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अनुसूची III का कॉलम (5) जो प्रत्यक्ष भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित करता है, इस प्रकार "संदर्भ या निगमन द्वारा विधान" के सिद्धांतों पर अनुसूची IV का एक हिस्सा बन जाता है। अतः ये योग्यताएं न केवल सीधी भर्ती के लिए बल्कि पदोन्नति के लिए भी लागू होंगी।

17. अनुसूची IV यह भी इंगित करती है कि समूह प्रशिक्षक/तकनीकी सहायक / जूनियर एडवाइजर अप्रेंटिसशिप/मिल राइट फोरमैन, अधीक्षक, तकनीकी जिनके पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, वे केवल वाइस-प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने 10 साल की सेवा दी हो।

18. इस प्रकार, नियम विशेष रूप से दोनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करते हैं समूह, अर्थात्, जिनके पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा है और जिनके पास यह योग्यता नहीं है। जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा है, उन्हें प्रिंसिपल, कक्षा II और अनुसूची IV में बताए गए अन्य उच्च पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है, जबकि जिनके पास ऐसी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, उन्हें केवल वाइस प्रिंसिपल के पद तक पदोन्नत किया जा सकता है।

19. मान लीजिए, प्रत्यर्थी के पास कोई इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। उनके पास क्राफ्ट में डिप्लोमा है और परिणामस्वरूप वे प्रिंसिपल, कक्षा II या कक्षा I के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं थे।

20. ट्रिब्यूनल सेवा नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में नोटिस करने में विफल रहा और गलत दृष्टिकोण पर प्रतिवादी के दावे को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा कि डिग्री या डिप्लोमा रखने की आवश्यकता को पदोन्नति के माध्यम से नियुक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

21. प्रधानाचार्य का पद चाहे वह द्वितीय वर्ग का हो या प्रथम वर्ग का, एक उच्च जिम्मेदारियों का पद है। प्रशासनिक गुण उम्मीदवारों की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ मिश्रित और मिले जुले होते हैं और इसलिए, नियमों में, विशेष रूप से उससे जुड़ी अनुसूची में यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि उम्मीदवार, चाहे उन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाना हो या पदोन्नति द्वारा, इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।

22. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी को पहले से ही प्रिंसिपल, वर्ग II के पद पर पदोन्नत किया गया था और नियमों की घोषणा से पहले वर्ग I के प्रिंसिपल के पद पर भी रखा गया था, प्रिंसिपल के रूप में उनकी पदोन्नति को बाधित नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि नियम यह उस स्थिति पर लागू होगा जहां पद खाली पड़ा था और नियमों की घोषणा के बाद इसे भरने का इरादा था। यह भी तर्क दिया जाता है कि 1976 से प्राचार्य के पद पर काम करने के

बाद, उन्हें उच्च पद पर इतनी लंबी अवधि की समर्पित सेवा के बाद उपाध्यक्ष के पद पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ये तर्क योग्यता से रहित हैं।

23. यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी को प्राचार्य वर्ग II के पद पर पदोन्नत किया गया था छह महीने की छोटी अवधि के लिए या आयोग द्वारा विधिवत चुने गए उम्मीदवारों की उपलब्धता तक, जो भी पहले हो। यह भी विवादित नहीं है और न्यायाधिकरण ने स्वयं इसे एक तथ्य के रूप में पाया है कि प्रतिवादी को केवल एक तदर्थ क्षमता में प्राचार्य के पद पर रखा गया था। नतीजतन, पद, नियम के अनुसार नियमित आधार पर नहीं भरा गया है, अपीलार्थी द्वारा इसे रिक्त माना जाना उचित था। ऐसा होने पर, प्रत्यर्थी के पास केवल तदर्थ दर्जा था जिसे वह तब तक बनाए रखेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसे बदल नहीं दिया जाता।

24. सरकारी सेवा अनिवार्य रूप से स्थिति का मामला है न कि अनुबंध का। रोशन लाल टंडन बनाम भारत संघ, [1968] 1 एस. सी. आर. मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नानुसार अवलोकन किया था:

"यह सच है कि सरकारी सेवा की उत्पत्ति संविदात्मक है। वहाँ हर मामले में एक प्रस्ताव और स्वीकृति है। लेकिन एक बार अपने पद या कार्यालय में नियुक्त होने के बाद सरकारी सेवक एक दर्जा प्राप्त कर लेता है और उसके अधिकार और दायित्व अब दोनों की सहमति से निर्धारित नहीं होते बल्कि कानून या वैधानिक नियमों द्वारा जिन्हें सरकार द्वारा एकतरफा बनाया और बदला जा सकता है। दूसरे शब्दों

में, सरकारी कर्मचारी की कानूनी स्थिति का अनुबंध की तुलना में अधिक दर्जा होता है। स्थिति की पहचान अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध से है जो कि कानूनी सार्वजनिक कानून द्वारा लगाया गया है, न कि केवल दलों के समझौते द्वारा नहीं। सरकारी कर्मचारी की सेवाओं की परिलब्धियाँ और शर्तें कानून या वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती हैं जिन्हें कर्मचारी की सहमति के बिना सरकार द्वारा एकतरफा बदला जा सकता है। यह सच है कि अनुच्छेद 311 अनुच्छेद 310 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई हटाने की शक्ति पर संवैधानिक प्रतिबंध लगाता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार और उसके सेवक के बीच का संबंध एक मालिक और नौकर के बीच सेवा के सामान्य अनुबंध जैसा नहीं है। कानूनी संबंध पूरी तरह से अलग है, स्थिति से हटकर कुछ है। यह दलों के बीच स्वेच्छा से दर्ज किए गए विशुद्ध संविदात्मक रिश्ते से कहीं अधिक है। स्थिति के कर्तव्य कानून द्वारा तय किए जाते हैं और इन कर्तव्यों को लागू करने में समाज का हित होता है। न्यायशास्त्र की भाषा में प्रस्थिति किसी समूह की सदस्यता की एक शर्त है जिसकी शक्तियाँ और कर्तव्य विशेष रूप से कानून द्वारा निर्धारित होते हैं न कि सम्बन्धित दलों के बीच समझौते से।"

25. इन टिप्पणियों को एक अन्य संविधान पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था भारत संघ और अन्य बनाम तुलसीराम पटेल, एआईआर (1985) डी

एससी 1416 [1985] 3 एससीसी 398 -- [1985] सप. 2 एससीआर 131. दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस में एक 9-न्यायाधीशों की पीठ ने, एआईआर (1991) एससी 101 [1991] सप. 1 एससीसी 600 [1990] सप. 1 एससीआर 142 रोशन लाल टंडन के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों को भी मंजूरी दी कि सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच कानूनी संबंध पूरी तरह से अलग है। यह विशुद्ध रूप से संविदात्मक संबंध से कहीं अधिक है और 'स्थिति' की प्रकृति में है।

26. क्या कोई व्यक्ति किसी विशेष पद पर एक महत्वपूर्ण क्षमता में है या केवल अस्थायी है या तदर्थ एक ऐसा प्रश्न है जो सीधे उसकी स्थिति से संबंधित है। यह सब नियुक्ति की शर्तों पर निर्भर करता है। यह किसी सरकारी कर्मचारी के लिए खुला नहीं है कि स्थिति के स्वतः परिवर्तन का दावा करेगा जब तक कि वैधानिक नियमों में कुछ प्रावधानों द्वारा परिणाम की विशेष रूप से परिकल्पना नहीं की गई है। इसलिए, जब तक किसी विशेष परिस्थिति में स्थिति में बदलाव के लिए वैधानिक नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, तब तक किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए उस स्थिति से भिन्न स्थिति का दावा करना खुला नहीं है जो उसे सेवा के प्रारंभिक या बाद के चरण में प्रदान की गई थी।

27. तत्काल मामले में इन सिद्धांतों को लागू करना, क्योंकि प्रतिवादी, माना जाता है, एक तदर्थ क्षमता में नियुक्त किया गया था, वह उस क्षमता में विचाराधीन पद धारण करना जारी रखेगा। अतः नियमों की घोषणा पर, प्रधानाचार्य का पद जो उनके पास था, नियमित रूप से भरा जाना माना नहीं जा सकता था और इसे खाली माना

जाना था। उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियमित नियुक्त के लिए, योग्य उम्मीदवार पर विचार किया गया, और प्रत्यर्थी, जिसके पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं थी, को प्राचार्य के पद के लिए योग्य या उपयुक्त नहीं पाया गया और परिणामस्वरूप उसे नियमित रूप से उप-प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया क्योंकि वह केवल उस पद के लिए मुख्य रूप से इस कारण से उपयुक्त पाया गया कि उसके पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा नहीं था।

28. इसके बाद प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यद्यपि प्रत्यर्थी के पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, वह लंबे समय से प्राचार्य के पद पर काम कर रहा है और चूंकि उसने उस पद पर पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है, इसलिए आवश्यकता नहीं है इन परिस्थितियों में, उन्हें उप-प्राचार्य के रूप में वापस करने के परेशान करने की। यह याचिका भी बेमानी है।

29. नियम 8 (2), जो शैक्षिक योग्यता की अनिवार्य शर्तें प्रदान करता है, और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि "उम्मीदवारों के पास अनुसूची III में दिखाए गए अनुसार सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए"। अनुसूची III के कॉलम 2 में, प्रिंसिपल वर्ग 1 और प्रिंसिपल वर्ग II के पदों का उल्लेख किया गया है और उसके कॉलम 5 में, यह फिर से अनिवार्य शब्दों में उल्लेख किया गया है कि "उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना

चाहिए और साथ ही किसी भी प्रशिक्षण संस्थान या किसी प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्था में काम करने का पांच साल का अनुभव होना चाहिए।"

30. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि उल्लेखित शैक्षिक योग्यताएँ प्रचार्य वर्ग I या प्राचार्य वर्ग II के पद के लिए अनुसूची III के कॉलम 5 में पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों पर भी लागू होते हैं और अनुसूची III के कॉलम 5 की प्रयोज्यता प्रत्यक्ष नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं है। इस स्थिति में, इसलिए, किसी व्यक्ति के प्राचार्य वर्ग II या प्राचार्य वर्ग I के पद पर पदोन्नत होने के लिए पात्र होने से पहले, उसके पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।

31. याचिका कि न्यायालय का "मानवीय दृष्टिकोण" होना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए जो पहले से ही एक दशक से अधिक समय से इस पद पर काम कर रहा है, उसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अदालतें शायद ही भावनात्मक अपीलों से प्रभावित होती हैं। वादकारी पक्षकारों को न्याय प्रदान करने में, न्यायालय न केवल संबंधित मामलों के गुण-दोष में जाते हैं, वे समानताओं को संतुलित करने का भी प्रयास करते हैं ताकि उनके बीच पूर्ण न्याय हो सके। इस प्रकार न्यायालय हमेशा एक मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। तत्काल मामले में भी, इस दृष्टिकोण से अलग नहीं किया गया है। हम पूरी तरह से सचेत हैं कि प्रतिवादी ने काफी लंबे समय तक विचाराधीन पद पर काम किया था, लेकिन यह केवल तदर्थ क्षमतामें था। हम समान रूप से जागरूक हैं कि एक चयनित उम्मीदवार जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध है। इस स्थिति में, यदि प्रत्यर्थी को केवल

"मानवीय दृष्टिकोण" की उनकी अवधारणा, के आधार पर इस पद पर बने रहने की अनुमति है , तो यह एक विधिवत चयनित उम्मीदवार की कीमत पर होगी जो उस रोजगार से वंचित होगा जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया था और अंततः चयनित हुआ था। वास्तव में, यह "मानवीय दृष्टिकोण" है। जिसके लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति पर चयनित उम्मीदवार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है जिसके पास आवश्यक योग्यता भी नहीं है। न्यायालय और न्यायाधिकरण को भी नियमों के अनिवार्य प्रावधानों की अवहेलना करने की कोई शक्ति नहीं है सहानुभूतिपूर्ण विचार पर कि एक व्यक्ति, हालांकि आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है, को केवल पद पर बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए अपने अनुभव के आधार पर। इस तरह का आदेश संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सरकार द्वारा बनाए गए सांविधिक प्रावधानों को बदलने या संशोधित करने के बराबर होगा।

32. प्रत्यर्थी द्वारा एक दशक से अधिक समय से कार्य के कारण प्राप्त अनुभव विचाराधीन पद पर किसी उम्मीदवार के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं के होने के साथ तुलना उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता से नहीं की जा सकती है। यदि सरकार ने अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ पदों का सृजन किया है, तो उन पदों पर नियुक्त होने से पहले उम्मीदवारों की नियुक्ति का तरीका या योग्यता निर्धारित करनी होगी। योग्यता स्वाभाविक रूप से पदों की प्रकृति या सरकार द्वारा बनाई गई सेवा के अनुसार भिन्न होगी।

33. विचाराधीन पद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानके प्राचार्य का पद है। सरकार ने इस पद के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा निर्धारित किया है। जिन लोगों के पास यह योग्यता नहीं है, उन्हें इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता का पद की प्रकृति के साथ सीधा संबंध है। प्रधानाचार्य का हो सकता है कक्षा लेने और छात्रों को पढ़ाने का भी अवसर भी पड़े। एक व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, वह संभवतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों को इंजीनियरिंग विषय और इसकी विभिन्न शाखाओं की तकनीकी चीजों को नहीं पढ़ा सकता है।

34. उत्तरदाता ने पद पर एक तदर्थ क्षमता में करते हुए हो सकता है कि प्राचार्य ने कुछ प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया हो, लेकिन इसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके ज्ञान के बराबर नहीं माना जा सकता है। एक कम्पाउंडर, जो आधुनिक चिकित्सा में अभ्यास करने वाले डॉक्टर के साथ काफी लंबे समय तक बैठा रहता है, हो सकता है कि उसने विभिन्न रोगों या बीमारियों के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा का निरीक्षण करके कुछ अनुभव प्राप्त किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह, उस प्रक्रिया से, मानव शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान या औषध विज्ञान के सिद्धांतों या शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र का, किसी विशेष दवा की क्रिया या उसके दुष्प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करता है। केवल अनुभव के आधार पर कम्पाउंडर विशेष रूप से एमबीबीएस या चिकित्सा या शल्य चिकित्सा में अन्य उच्च डिग्री रखने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित एक पद का दावा नहीं कर सकता। इसलिए, अनुभव की याचिका विफल होना चाहिए। इसके अलावा, यह शैक्षिक योग्यता से संबंधित नियमों में ढील देने के बराबर होगा।

नियम में ढील देने की शक्ति निहित है विशेष रूप से राज्यपाल में, जैसा कि नियम 21 द्वारा प्रदान किया गया है। इस शक्ति को न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा हड़पा नहीं जा सकता है।

35. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, अपील की अनुमति है, और एम. पी. प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांकित 19.4.1994 आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रतिवादी की दावा याचिका को खारिज कर दिया जाता है लेकिन लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।